MR. CHAIRMAN: Please allow the Question Hour to proceed. ...*(Interruptions)*... Please resume your places. ...*(Interruptions)*... Question No. 102. ...*(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: Sir, in protest we are walking out. ...*(Interruptions)*...

(At this stage some hon. Members left the Chamber.)

सरकारी क्षेत्र के संस्थानों द्वारा दालों का आयात

*102. **श्री राज मोहिन्दर सिंह** मजीठा:††

डा. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि देश में दालों की उपभोक्ता मांग को पूरा करने और उनके मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकारी क्षेत्र के संस्थानों द्वारा दालों का आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्रमश: वर्ष 2005, 2006, 2007 और 2008 में सितम्बर माह तक किस-किस संस्थान द्वारा तथा कितनी-कितनी मात्रा में दालों का आयात किया गया है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान भारत में आयात के पश्चात् प्रत्येक दाल का औसत मूल्य कितना रहा; और

(घ) इन संस्थानों द्वारा आयातित दालों को देश में किस मूल्य पर बेचा गया?

कृषि, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् राज्य व्यापार निगम, पी ई सी लिमिटेड, खनिज एवं धातु व्यापार निगम तथा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (नेफेड) से 2006-07, 2007-08 और 2008-09 में दालें आयात करने को कहा है। वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा नेफेड द्वारा किए गए आयात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 (16-10-2008 तक) के दौरान आयात की गई दालें

(मात्रा मीट्रिक टनों में)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2006-07	2007-08	2008-09 (16-10-08 तक)
एस टी सी	-	364344	169664
एम एम टी सी	-	274292	69747
पी ई सी	-	429901	91940
नेफेड	49,300	249079	20996
योग	49,300	1317616	352347

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों ने विभिन्न देशों में, विभिन्न समयावधि में और विभिन्न मूल्यों पर सप्लायरों के साथ दालों के आयात की संविदाएं की हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 (16-10-2008 तक) के दौरान आयातित दालों के औसत खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य नीचे की तालिका में दिए गए है":-

††सभा में यह प्रश्न श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा द्वारा पूछा गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वर्ष 2006-07, 2007-08 **और** 2008-09 (16-10-2008 **तक**) **के दौरान आयात की गई दालों के औसत खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य**

(रुपए प्रति मीट्रिक टन में)

दालें	2006-07		2007-08	2008-09 (16-10-2008 तक)		
	औसत खरीद मूल्य	औसत बिक्री मूल्य	औसत खरीद मूल्य	औसत बिक्री मूल्य	औसत खरीद मूल्य	औसत बिक्री मूल्य
उड़द	31495	34170	25893	23409	28094	27452
तूर	-	-	22577	21867	32577	29048
मूंग	31913	27800	29008	19841	31997	28675
मसूर	-	-	26753	30857	-	-
देसी चना	-	-	25523	24693	32370	24693
येलो पीज	-	-	15699	16654	25068	-
डन पीज	-	-	21741	22091	-	-

Import of pulses by Public Sector Institutions

†*102. SHRI RAJ MOHINDER SINGH MAJITHA:††

DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that pulses have been imported by public sector institutions to meet the demand of pulses by consumers and control their prices in the country;

(b) if so, the names of the institutions which have imported pulses and the quantity of pulses imported by them in the years 2005, 2006, 2007 and till September, 2008;

(c) the average cost of each pulse after its import in India during the said period; and

(d) the cost at which imported pulses were sold by these institutions in the country?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir. Government has asked Public Sector Undertakings, namely, State Trading Corporation (STC), PEC Ltd., Minerals and Metals Trading Corporation (MMTC) as well as National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd., (NAFED) to import pulses in 2006-07, 2007-08 and 2008-09. Details of import by PSUs and NAFED during 2006-07, 2007-08 and 2008-09 are given below:

†Original notice of the question was received in Hindi.

†† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Raj Mohinder Singh Majitha.

Pulses imported during 2006-07, 2007-08 and 2008-09 (up to 16.10.08) by PSUs

(Qty. in metric tonnes)

PSUs	2006-07	2007-08	2008-09 (upto 16.10.08)
STC	-	364344	169664
MMTC	-	274292	69747
PEC	-	429901	91940
NAFED	49,300	249079	20996
TOTAL	49,300	1317616	352347

(c) and (d) The public sector agencies have contracted imports of pulses with suppliers in different countries, at different periods of time and at different prices. The average purchase price and sale price of imported pulses during 2006-07, 2007-08 and 2008-09 (up to 16.10.08) by PSUs is given in Table below.

Average purchase price and sale price of imported pulses during 2006-07, 2007-08 and 2008-09 (up to 16.10.08) by PSUs

(Rs per metric tonne)

Pulses	2006-07		2007-08		2008-09 (up to 16.10.08)	
	Avg. Purchase price	Avg. sale price	Avg. Purchase price	Avg. sale price	Avg. Purchase price	Avg. sale price
Urad	31495	34170	25893	23409	28094	27452
Tur	-	-	22577	21867	32577	29048
Moong	31913	27800	29008	19841	31997	28675
Masoor	-	-	26753	30857	-	-
Desi Chana	-	-	25523	24693	32370	24693
Yellow peas	-		15699	16654	25068	-
Dun peas	-	-	21741	22091	-	-

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा: चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से इंफोरमेशन चाहूंगा। सर, देश में दाल आम आदमी के भोजन के लिए महत्वपूर्ण है, मगर दुर्भाग्य तो यह है कि दाल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने पिछले बीस से अधिक सालों से योजनाएं तो लागू करने का दावा किया और राष्ट्रीय, नेशनल लेवल पर एक दाल उत्पादन मिशन भी बनाया, जिसको बने इतना अधिक समय हो गया है, परन्तु आज भी दालों के मामले में देश को आत्म-निर्भर नहीं बनाया गया है। मैं जानना यह चाहता हूं कि सरकार दालों की मांग को पूरा करने के लिए इम्पोर्ट तो करती है, लेकिन जहां इम्पोर्ट करके दालों की कमी को पूरा करती है, वहीं क्या दालों की कीमतों में कमी करने के लिए सरकार ने पिछले तीन सालों में क्या-क्या कदम उठाए हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ा है? मैं यह भी जानना चाहता हूं।

श्री सभापति: एक सवाल पूछिए।

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा: सर, दो सवाल।

श्री सभापति: नहीं, एक सवाल।

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा: ठीक है, तो पूछ लिया।

श्री शरद पवार: सभापति महोदय, देश में दालों का उत्पादन कम हुआ, ऐसी बात नहीं है। अगर आप प्रोडक्शन की फिगर्स देखेंगे, तो the pulses production in the country increased from 13.13 million tonnes in 2004-05 to 14.99 million tonnes and this year, to 15.11 million tonnes. So, there is substantial improvement in production. But I have to admit that there is a gap between demand and supply. The demand for this year was 16.77 million tonnes and the production was 15 and odd million tonnes. So, there is a gap of about 1.3 million tonnes. There is no alternative left to fill this gap but to import, and we have to see to it that the prices are maintained at a proper level and the availability of pulses is ensured. On the one hand, that action has been taken by the Government and, on the other, there are a number of schemes which have been introduced to enhance the production of pulses. In particular, we are trying to expand the cultivable area of pulses. Secondly, we have taken steps to introduce some new schemes such as the National Food Security Mission and the Rashtriya Krishi Vikas Mission. Under the National Food Security Mission, there is a production of Rs. 5000 crores and we are concentrating on enhancing the production of wheat, rice and pulses. Then, for the Rashtriya Krishi Vikas Mission in the next five years – in fact, one year is already gone; in four years – the total amount which Government of India would like to spend is more than Rs. 25000 crores, and the States have been asked to submit proposals to enhance the production of all these cereals.

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा: सर, अपने सैकंड सप्लिमेंट्री के रूप में मैं जानना चाहता हूं कि जिन संस्थानों ने दालों का पिछले बीस एक सालों में इम्पोर्ट किया है, उन संस्थानों में हरेक संस्था ने इन दालों के इम्पोर्ट और उनकी बिक्री के कारोबार में कितना-कितना लाभ कमाया है और हरेक साल में सरकार ने संस्थाओं को इस मद में कितनी-कितनी सब्सिडी दी है? ये जो black marketing करते हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताया जाए, क्योंकि ये जितनी संस्थाएं हैं ये दालें अपने पास रखकर फिर black market में बेचती हैं।

श्री शरद पवार: ये सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की organisations हैं, जिनको इम्पोर्ट करने की इजाजत दी गई है, जिसमें MMTC, STC, State Trading Corporation, NAFED, which is a cooperative organisation, and PEC are included. All these organisations are Government organisations. The Government of India has asked them to import and it has also assured them that 15 per cent of whatever losses they would incur would be borne by Government of India and that their job is to make foodgrains available in the market. We have not finalised the policy as to the exact rate at which they should sell. But we had constituted the Board and that Board must take a decision and see to it that these pulses are sold in a transparent manner. Except one item, everywhere they have been bought at a particular price and sold it at a lesser price which has been made available to the public.

डा. मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि दाल प्रोटीन के लिए हिन्दुस्तान का staple food है। अभी पहले प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पिछले साल तक, 2007 -08 तक, दालों का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन मेरे सामने एक बयान है, जो Pulse Importers' Association के

अध्यक्ष हैं, वे कहते हैं कि, "According to the Government's fourth advance estimate, production of pulses is expected to decline by 27 per cent at 4.72 million tonnes in the Kharif against 6.45 million tonnes in the last session". तो खरीफ की दालें बड़ी इम्पोर्टेंट है, जिनमें उड़द, अरहर, मूंग, चना आदि हैं। फिर आगे वे कहते हैं कि सरकार ने import की इजाजत दी है और दस रुपया प्रति किलोग्राम subsidised करने के लिए भी कहा है। अगर यह सच है तो हालात बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि हमारे सवाल के जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह जो imported दालें हैं, इनका औसत खरीद मूल्य उड़द की दाल का 28,094 per metric ton है, यानी लगभग 28.00 रुपए प्रति किलोग्राम और औसत बिक्री मूल्य 27.50 रुपए प्रति किलोग्राम है, लेकिन बाजार भाव 60.00 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा है। फिर अरहर की दाल जो सबसे ज्यादा खाई जाती है, उसका औसत खरीद मूल्य 32 रुपए प्रति किलोग्राम है और बिक्री मूल्य है 29 रुपए, इस मूल्य पर आपकी इंपोर्ट करने वाली संस्थाएं दे रही हैं, लेकिन बाजार में उसका दाम 52 रुपए किलो है। इसलिए यह समझ में नहीं आता है कि आप subsidize भी कर रहे हैं और आपकी संस्थाएं 29 रुपए और 27 रुपए प्रति किलोग्राम पर दाल दे रही हैं, लेकिन बाजार में उसका भाव 60 रुपए किलो और 52 रुपए किलो आ रहा है। इसी तरह से मूंग का इंपोर्टेड दाम 31 रुपए किलो या 32 रुपए किलो है और 28.68 रुपए पर आपकी संस्थाएं बाजार में यह दाल दे रही हैं, लेकिन मुझे यह दाल 60 रुपए प्रति किलो के दाम पर मिल रही है। इसी तरह से देसी चने का खरीद मूल्य 24 रुपए प्रति किलो आता है और हमें यह 48 रुपए किलो पर मिल रहा है। इस तरह से यह हमें दुगुने भाव पर मिल रहा है। यह दुगुना मार्जिन कहां से आ रहा है? इस तरह गरीब आदमी की जेब काटी जा रही है, क्योंकि यह सिवाय दाल और रोटी के कुछ खाता नहीं है और यह कहना कि सब चीजें ठीक हैं, हर चीज दुरुस्त है, मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह गड़बड़ कैसे हो रही है? आप यह कहकर नहीं बच सकते कि हमने तो उनको दे दिया, वे transparent ढंग से चाहे जिसकी जेब काट लें। जेब आप चाहे पीछे से काटें, चाहे transparent ढंग से काटें ...(**व्यवधान**)... आपने उनको जेब काटने की इजाजत दे दी है।

श्री सभापति: आपने सवाल पूछ लिया है, अब जवाब सुन लीजिए ...(**व्यवधान**)...

डा. मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बाजार भाव को नियंत्रित करने के लिए और आम आदमी को सही और उचित मूल्य पर दाल उपलब्ध कराने के लिए क्या आपकी कोई नीति है? यदि आप इन जमाखोरों को सब्सिडी देने के बजाय, आम आदमी को दे सकते हैं, तो कैसे देंगे, इसके बारे में मैं सरकार की नीति स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं।

श्री शरद पवार: सभापति जी, मैंने शुरू में ही कहा है कि देश की total requirement और availability में 1.4 मिलियन टन की कमी है। जो टोटल इंपोर्ट हुआ, उसको देखने के बाद पता चला है कि जितना गैप है, उतना इंपोर्ट नहीं हुआ है। जो कुछ इंपोर्ट हुआ है, वह किस रेट पर बेचा है, इसके बारे में मैंने सदन के सामने पूरी जानकारी दी है। इससे एक बात साफ होती है कि जिस रेट से खरीदा, उससे कम रेट पर पब्लिक सैक्टर आर्गनाइजेशंस ने बेचा है, फिर भी जितनी availability चाहिए, उतनी नहीं है, यह बात साफ है। इसका रास्ता निकालने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, यह बात सच है कि हमने एक नयी नीति का प्रस्ताव किया है जो PDS है, इसके हर कार्ड पर एक किलो पर मार्केट रेट से 10 रुपए कम कीमत पर, यानी 10 रुपए की सब्सिडी देकर हम दाल available कराना चाहते हैं और इसके लिए जो availability चाहिए, इसके लिए जो इंपोर्ट करना पड़ेगा, वह इंपोर्ट हम करेंगे और इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद हम लेंगे। यह नीति निर्धारण अभी फाईनल स्टेज में है और मुझे लगता है कि हम महीने-डेढ़ महीने में इसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देंगे, जिससे आम आदमी को यह दाल राशन की दुकान पर कम कीमत पर मिलने का एक नया रास्ता खुल जाएगा।

डा. मुरली मनोहर जोशी: तब तक आप इन लोगों को जेब काटने की छूट देते रहेंगे ...(**व्यवधान**)... सवाल तो यह है कि ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंह: सर, answer आना चाहिए, आप answer दिलवाइए ...(**व्यवधान**)...

डा. मुरली मनोहर जोशी: इसका मतलब यह है कि जो इंपोर्ट करने वाली संस्थाएं हैं और जो बाजार में wholesale पर खरीदते हैं, उनमें एक connivance है, मिलीभगत है। वह पैसा कहां जा रहा है? यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि where is that money going?

SHRI SHARAD PAWAR: It is a simple thing. As I have already given him the reply as to what is the average purchase price and what is the selling price. For instance, for *toor*, the purchase price is Rs.23,577 and the selling price is Rs.21,800. For *moong*, the purchase price is Rs.29,000 and selling price is Rs. 19,000. Except for *masoor* and *urad*, everywhere, you will see that the selling prices are definitely less than the purchase price. The Government has taken that hit and has made that available. But, it is true that there is still a gap in the market. Prices are high. Recently, MSP also has been enhanced. In that situation, if we have to bring the prices down and if we have to make availability for public, especially the weaker sections, there is no alternative except to make these things available in the Public Distribution System and we are on that process.

श्रीमती विप्लव ठाकुर: सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि ये जो 15.11 मिलियन टन दालें खरीदतें हैं, उसमें इन्होंने बता दिया कि बाहर से तो पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनियां खरीद रही हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहती हूं कि भारत में ये किसानों से किस एजेंसी के द्वारा दालें खरीदते हैं? जैसे गेहूं और चावल, तो फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से किसानों से खरीदते हैं। ये दालें किस एजेंसी से ली जाती हैं? दूसरी बात यह है कि ये दालें किसानों से किस भाव से ली जाती हैं? मेरा एक और सवाल है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: सिर्फ एक सवाल प्लीज़।

श्रीमती विप्लव ठाकुर: जो integrated scheme है, उसमें इन्होंने पैसा नहीं बताया है कि इन pulses के लिए कितना पैसा रखा गया है। यह भी बताने की कृपा करेंगे।

श्री शरद पवार: महोदय, इस देश में जो procurement की policy है, इसके दो हिस्से हैं। एक Food Corporation of India है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट की procurement एजेंसीज हैं। इन दोनों की मदद लेकर गेहूं और चावल का procurement अपने देश में होता है। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। बाकी जो items हैं, उनके procurement की आवश्यकता पड़ती है। जहां तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एक बार कोई एग्रीकल्चर कमोडिटी की मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार द्वारा घोषित कर दी जाती है तो उसके बाद जब मार्केट में उसकी कीमत मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे आती है, तब भारत सरकार किसानों को राहत देने के लिए मार्केट इन्टरवेंशन करती है। जहां तक दालों की कीमत है, भारत सरकार ने इसके लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित की है, इससे ऊपर आज मार्केट प्राइस है, इसलिए आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर दालों को खरीदने की आवश्यकता नहीं है और भारत सरकार अपने देश के किसानों से दाल नहीं खरीदती है। इसके खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि आज किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा कीमत मिल रही है।

श्रीमती विप्लव ठाकुर: यह नहीं बताया गया कि उसमें कितना पैसा रखा गया है?

श्री पुरुषोत्तम खोडाभाई रूपाला: सर, विदेशों से ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आपका जब नंबर आएगा, तब आप बोलिएगा ...(**व्यवधान**)... Just one minute please. I have not called the hon. Member. Please ask the question when your name is called.

श्रीमती विप्लव ठाकुर: सभापति महोदय, मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है।

MR. CHAIRMAN: Please, it's over....*(Interruptions)*...

श्री पुरुषोत्तम खोडाभाई रूपाला: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहूंगा, उन्होंने बताया कि जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कीमत गिर जाती हैं तभी देश के किसानों से दाल वगैरह खरीदने का प्रश्न उपस्थित होता है। अभी बाजार में मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा कीमत किसानों को मिल रही है। मैं यह जानना चाहता हूं आप जो आयात कर रहे हैं, उसकी कीमत और जो किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद करते हैं, उसमें कितना अंतर है? क्या सरकार यह चाहती है कि हम जिस कीमत पर विदेशों से आयात कर रहे हैं, उसी कीमत पर हमारे किसानों से खरीदा जाए? इस संबंध में सरकार की क्या राय है?

श्री शरद पवार: महोदय, सिम्पल बात यह है कि देश में जितनी डिमाण्ड है, उतनी सप्लाई नहीं हो पाती है। जितनी आवश्यकता है, उतनी वह देश में पैदा नहीं होती है। इस गैप को भरने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा, तभी हम यहां के स्थानीय लोगों को राहत दे सकते हैं। इसी गैप को भरने के लिए हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। इम्पोर्ट करने से हमें कोई खुशी नहीं होती है, मगर consumer का interest भी safeguard करना पड़ता है, इसलिए इम्पोर्ट करना पड़ता है। जो इम्पोर्ट प्राइस है और यहां की जो मार्केट प्राइस है, इसमें फर्क है। आज इम्पोर्ट प्राइस यहां की मार्केट प्राइस से कम है। यहां के किसानों को इससे ज्यादा कीमत मिलती है, इसलिए सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कोई देने को राजी नहीं है। वह कोई देगा भी नहीं और सरकार भी नहीं खरीदेगी, क्योंकि इस तरह से किसानों को अच्छी कीमत मिलती है तो सरकार क्यों उनसे खरीदेगी? आज की स्थिति में हम उनसे नहीं खरीदते हैं, जब मार्केट प्राइस मिनिमम, सपोर्ट प्राइस से नीचे आएगी, तब हम मार्केट में एंटर करेंगे और इंटरवीन करके हम खरीदेंगे व किसानों को राहत देंगे।

श्री शरद यादव : सभापति जी, जो सारे सवाल किए गए हैं, मैं मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर में STC है, PEC है, MMTC है और NAFED है, इनके जरिए आप खरीद करते हैं। नेफेड को जो जिम्मा दिया गया था, उससे बाहर उसने अरबों रुपए पेंटिंग और कई तरह के धंधे में लगा दिए और आपने इस मामले को सीबीआई को दिया हुआ है, लेकिन आज तक इसका कोई पता नहीं है। आप एक वरिष्ठ मंत्री है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस मामले में आप क्या कर रहे हैं? कहां जगह खोजी है? सभापति जी, अरबों रुपए... उसके अध्यक्ष भी स्वर्गीय हो गए, लेकिन इतने वर्षों से, दो-तीन साल से यह नैफेड खुला है, अभी तक उसके मामले में क्या हुआ है? क्योंकि इनको आपने फिर से यह धंधा दे दिया है, लेकिन इन लोगों के ऊपर किस तरह के काम हैं, क्या आपने इस मामले में कोई पहल की है? आगे जांच होगी या नहीं होगी? यह पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा? इसलिए मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि इस मामले में स्थिति क्या है?

श्री शरद पवार: मान्यवर, यह सवाल है दालों के इम्पोर्ट के बारे में, लेकिन माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, वह नैफेड का कारोबार किस तरह से चलता है और दाल छोड़कर दूसरे क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, इस बारे में है। मेरे पास इसकी information है, लेकिन technically इसके लिए मुझे separate notice की आवश्यकता है। यदि मान्यवर सदस्य को इसकी information चाहिए, तो मैं देने के लिए तैयार हूं। यह बात सच है कि लोक सभा के जनता दल (यू) के एक सदस्य थे, जिनके नेतृत्व में यह संगठन चलता था। उस जमाने में नैफेड ने एक resolution करके जो इनके ऊपर जिम्मेदारी है agricultural produce खरीदने की, वह agricultural produce छोड़कर non-agricultural sector में पैसा देने का, धंधा करने का एक नया कारोबार शुरू किया। इसमें कई कंपनियों को उन्होंने एडवांस दे दिया और एडवांस देने के बाद जब ऑडिट में सरकार के सामने यह बात आ गई, तो सरकार ने इसकी जांच करने के लिए सी.बी.आई. को कहा और यह जांच अभी सी.बी.आई. के पास है और उनकी फाइनल रिपोर्ट आने के बाद जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। दुख की बात एक ही है कि जो इसके प्रमुख थे, उनकी बीच में accidental death हो गई, इसलिए उनकी तरफ से हमें जो ज्यादा information चाहिए, वह मिल नहीं रही है। यह नैफेड की आज की स्थिति है। इसका और दाल खरीदने का कोई संबंध नहीं है, यह अलग विषय है।